माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

वीना मंटरू-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य-प्रतिवादी

C.W.P. No. 1579/1989

19 सितंबर, 2007

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 - नियम 10 और 16 (2) (ए) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - 1976 में सहायक ग्रेड I में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के नाम पर विचार - उस समय याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप पत्र लंबित नहीं था - क्या बाद में आरोप पत्र जारी होने और लगाए गए सेंसर की सजा उसकी पदोन्नति में बाधा बन सकती है - माना गया, नहीं - याचिकाकर्ता को वास्तव में 1978 में पदोन्नत किया गया था लेकिन एच.पी. क्षेत्र में पद पर शामिल होने में विफल रही - याचिकाकर्ता ने निचले पद पर काम करना जारी रखा पंजाब क्षेत्र में और 1980 में पदोन्नत किया गया - क्या याचिकाकर्ता अपनी पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता का हकदार है - आयोजित, नहीं - एच.पी. में पदोन्नति पद पर शामिल होने में विफलता। क्षेत्र, याचिकाकर्ता पदोन्नति पद पर शामिल होने की तारीख से पहले वरिष्ठता की गणना करने का हकदार नहीं है।

याचिकाकर्ता को वर्ष 1976 में पदोन्नति के लिए विचार किया गया और पैनल में लाया गया। तब तक उनके ख़िलाफ़ कोई आरोपपत्र नहीं था. उसके बाद आरोप पत्र जारी करना और "निंदा" की सज़ा उसकी पदोन्नति में बाधा नहीं बन सकती और न ही होनी चाहिए। किसी भी मामले में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई थी या वापस ले ली गई थी। याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने का प्रतिवादी का यह आधार टिकाऊ नहीं है। हालाँकि, यह रिकॉर्ड पर तथ्य है कि याचिकाकर्ता को 12 सितंबर, 1978 को पदोन्नत किया गया था और उसे पदोन्नति पद पर हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह इस पद पर शामिल नहीं हुई और पंजाब क्षेत्र में निचले पद पर काम करती रही। उन्हें 11 अगस्त, 1980 को पंजाब क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता एच.पी. में पदोन्नति पद पर शामिल होने में विफल रही। क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में निचले पद पर काम करना जारी रखा, 12 सितंबर, 1978 से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते। उत्तरदाताओं ने पदोन्नति पद पर शामिल होने की तारीख से पहले किसी भी तारीख से वरिष्ठता के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया है। . (पैरा 7)

अमित चोपड़ा, एडवोकेट, याचिकाकर्ता. के लिए

प्रतिवादी के लिए कोई नहीं

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली *(मौखिक)*

(1) उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। सुनवाई की पिछली तारीख पर भी प्रतिवादी अनुपस्थित थे। तदनुसार, इस रिट याचिका पर उत्तरदाताओं की अनुपस्थिति में गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की गई है।

(2) याचिकाकर्ता को 6 जुलाई 1970 को प्रतिवादी संख्या 1 भारतीय खाद्य निगम में सहायक ग्रेड-III के रूप में चुना गया था। वर्ष 1972 में उसे सहायक ग्रेड-2 (मंत्रिस्तरीय) के रूप में पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता आगे थी 22 सितंबर, 1976 को सहायक ग्रेड- I के रूप में पदोन्नत किया गया। 22 सितंबर, 1976 के आदेश की प्रति अनुलग्नक पी-1 के रूप में रिट याचिका के साथ संलग्न है। यह आदेश इंगित करता है कि उन्हें मूल आधार पर नियुक्ति के लिए पदोन्नति पैनल में लाया गया था। पदोन्नति की प्रक्रिया भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) विनियम, 1971 (इसके बाद "1971 विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियम 10 में इंगित की गई है। पदोन्नति गैर-चयन के संबंध में उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जानी है। आदेश (अनुलग्नक पी-1) से यह भी प्रतीत होता है कि एक पैनल तैयार किया गया था और याचिकाकर्ता का नाम पदोन्नति पैनल के क्रम संख्या 9 पर था। पदोन्नत लोगों को संबंधित अधिकारियों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया। आदेश के पैराग्राफ 2 में यह भी शर्त थी कि अधिकारी की पदोन्नति संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा सतर्कता मंजूरी के अधीन है। उक्त आदेश में याचिकाकर्ता को पंजाब क्षेत्र में तैनात करने की मांग की गई थी। हालाँकि, 26 अगस्त, 1978 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया (अनुलग्नक पी-2) जिसके

तहत याचिकाकर्ता की पदोन्नति पद पर पोस्टिंग पंजाब क्षेत्र से बदलकर एच.पी. कर दी गई और उनके शामिल होने की तारीख 11 सितंबर, 1978 तक बढ़ा दी गई थी। इस शुद्धिपत्र के बाद 12 सितंबर, 1978 को एक औपचारिक पदोन्नति आदेश जारी किया गया (अनुलग्नक पी-3) जिसके तहत पदोन्नति का आदेश दिया गया।

याचिकाकर्ता को नियमित आधार पर सहायक ग्रेड- I (एम) के रूप में, उसे विशेष कर्तव्य अधिकारी, एच.पी. को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। क्षेत्र, शिमला को एजी-1 के रूप में तैनाती हेतु। उसकी पदोन्नति उसके ड्यूटी पर उपस्थित होने की तिथि से प्रभावी होनी थी। इस आदेश से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को 19 सितंबर, 1978 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहा है कि वह पंजाब क्षेत्र में पदोन्नति की हकदार थी, न कि एच.पी. में। उन्होंने पंजाब क्षेत्र में अपने समायोजन के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन उन्हें इंतजार कराया गया और कभी भी पंजाब क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एच.पी. में शामिल नहीं हुआ। क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में एजी-द्वितीय के रूप में तैनात रहे। अंततः, उन्हें 11 अगस्त, 1980 से पंजाब में एजी-I के रूप में तैनात किया गया। पार्टियों का यह स्वीकृत मामला है कि 11 अगस्त, 1980 से याचिकाकर्ता एजी-I के रूप में कर्तव्य निभाती रही। एजी-I (मंत्रिस्तरीय) की वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-4) प्रतिवादी-निगम द्वारा 23 अगस्त, 1979 को प्रसारित की गई थी, जैसा कि 21 दिसंबर, 1978 को था। इस वरिष्ठता सूची में, याचिकाकर्ता को क्रमांक पर रखा गया था। .ज्ञान चंद से 504 ऊपर। इस वरिष्ठता सूची में, याचिकाकर्ता की पदोन्नति की तारीख 18 नवंबर, 1976 दिखाई गई है। वह वरिष्ठता सूची

(अनुलग्नक पी-4) में दर्शाए अनुसार अपनी वरिष्ठता स्थिति से असंतुष्ट नहीं है। उपरोक्त वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-4) के बाद 31 अगस्त, 1982 (अनुलग्नक पी-5) की एक और वरिष्ठता सूची आई, जिसमें उनका नाम ज्ञान चंद से ऊपर क्रम संख्या 491 पर दिखाया गया था, जिसे क्रम संख्या 492 पर दिखाया गया था। याचिकाकर्ता भी इस वरिष्ठता सूची से संतुष्ट है। 1 नवंबर, 1985 को, एक और अनंतिम वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-6) 31 अक्टूबर, 1985 की वरिष्ठता के साथ प्रसारित की गई। इस वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-6) में, याचिकाकर्ता को वरिष्ठ पर दिखाया गया था। क्रमांक 563। याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता स्थिति से व्यथित है जैसा कि इस वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक पी-6) में दर्शाया गया है, उसने दावा किया कि उसे क्रमांक 427-आबोव ज्ञान चंद पर होना चाहिए था। वरिष्ठता की स्थिति से व्यथित होकर, उन्होंने 1987 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1604 दायर किया, जिसका निपटारा 14 जनवरी, 1988 के आदेश के तहत निम्नलिखित आदेशों के साथ किया गया।

"याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि 1 नवंबर, 1985 को प्रसारित सूची में उसका नाम 123 स्थान नीचे कर दिया गया है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री जी.सी. गर्ग ने तर्क दिया है कि यह वरिष्ठता सूची केवल अनंतिम है। इस तथ्य को श्री गुप्ता भी स्वीकार करते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता इस वरिष्ठता सूची के खिलाफ अभ्यावेदन दे सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, का निपटारा बहुत शीघ्रता से किया जाएगा, अधिमानतः तीन महीने के भीतर। इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।"

(3) इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने 29 जनवरी, 1988 को 22 सितंबर, 1976 से अपनी वरिष्ठता का दावा करते हुए एक विस्तृत अभ्यावेदन दिया। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन का निपटारा कर दिया गया है, - आक्षेपित आदेश के अनुसार दिनांक 27 अक्टूबर 1988 (अनुलग्नक पी-7), उनके प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया है और उन्हें 5 सितंबर 1980 से एजी-1 (एम) के रूप में वरिष्ठता प्रदान की गई है, जिस दिन याचिकाकर्ता को एजी के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। 1 (एम) पंजाब क्षेत्र में। यह आदेश (अनुलग्नक पी-7) है जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(4) याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि वह 22 सितंबर, 1976 यानी अपनी पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता की हकदार है, न कि 5 सितंबर, 1980 से जब उसे पंजाब क्षेत्र में वास्तविक पोस्टिंग दी गई थी। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता 1971 के विनियमों के विनियम 16 (2) (ए) पर भरोसा करता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जाएगी जिसमें उनके नाम विनियम 10 के अनुसार तैयार किए गए पैनल में उपस्थित हों। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह 22 सितंबर, 1976 से वरिष्ठता की हकदार थी।

(5) याचिकाकर्ता के दावे का उत्तरदाताओं द्वारा दो बिंदुओं पर विरोध किया गया है। सबसे पहले, वर्ष 1976 में जब याचिकाकर्ता को जोनल प्रमोशन कमेटी द्वारा पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, तो उसके खिलाफ एक सतर्कता मामला लंबित था। मामला साल 1974 में दर्ज किया गया था. सीबीआई जांच के आदेश दिये गये थे. सी.बी.आई. अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

की और अंततः, याचिकाकर्ता को वर्ष 1978 में "निंदा" की सजा दी गई। दूसरे, याचिकाकर्ता को 12 सितंबर, 1978 को पदोन्नति आदेश जारी किया गया था, लेकिन वह पदोन्नति पद पर अपने नए पोस्टिंग स्थान पर शामिल नहीं हुई और पंजाब क्षेत्र में निचले पद पर कार्य करते रहे।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में कहा है कि जांच के आधार पर उसे पदोन्नति पैनल पर लाए जाने की तारीख के बाद मई, 1977 में आरोप पत्र दिया गया था। वर्ष 1978 में "निंदा" की सजा भी दी गई थी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को उसकी वास्तविक पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति और वरिष्ठता से वंचित करने के लिए अनुशासनात्मक दंड लागू नहीं किया जा सकता है। आदेश (अनुलग्नक पी-1) से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को 22 सितंबर, 1976 को ही पैनल में लाया गया था। हालाँकि, उसे वास्तव में 12 सितंबर, 1978 को पदोन्नत किया गया था। इसलिए, उसकी पदोन्नति की वास्तविक तारीख केवल 12 सितंबर है। सितंबर, 1978, न कि 22 सितंबर, 1976, जैसा कि दावा किया गया है।

---

(7) यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ सतर्कता जांच शुरू होने के बाद 22 सितंबर, 1978 से पदोन्नति का हकदार है, अब कोई सवाल ही नहीं है। इसका निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया आदि बनाम के.वी. के मामले में किया गया है। जानकीरमन आदि, (1) कि पदोन्नति को केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि कर्मचारी के खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही लंबित है। उक्त लाभ से इनकार करने के लिए, उन्हें उस चरण में प्रासंगिक समय पर

लंबित होना चाहिए जब कर्मचारी को चार्ज-मेमो/चार्ज-शीट पहले ही जारी की जा चुकी हो। यदि आपराधिक कार्यवाही लंबित है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही आरोप-पत्र जारी होने की तारीख से और आरोप तय करने की तारीख से शुरू मानी जाएगी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को वर्ष 1976 में पदोन्नति के लिए विचार किया गया और पैनल में लाया गया। तब तक उनके ख़िलाफ़ कोई आरोप-पत्र नहीं था. उसके बाद आरोप-पत्र जारी करना और "निन्दा" की सज़ा उसकी पदोन्नति में बाधा नहीं बन सकती और न ही होनी चाहिए। किसी भी मामले में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई थी या वापस ले ली गई थी। याचिकाकर्ता को पदोन्नति से वंचित करने का प्रतिवादी का यह आधार टिकाऊ नहीं है। हालाँकि, यह रिकॉर्ड पर तथ्य है कि याचिकाकर्ता को 12 सितंबर, 1978 को पदोन्नत किया गया था और एच.पी. में शामिल होने के लिए कहा गया था। क्षेत्र में प्रमोशनल पोस्ट पर, लेकिन वह इस पद पर शामिल नहीं हुईं और पंजाब क्षेत्र में निचले पद पर काम करती रहीं। उन्हें 11 अगस्त, 1980 को पंजाब क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता एच.पी. में पदोन्नति पद पर शामिल होने में विफल रही। क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में निचले पद पर काम करना जारी रखा, 12 सितंबर, 1978 से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते। उत्तरदाताओं ने पदोन्नति पद पर शामिल होने की तारीख से पहले किसी भी तारीख से वरिष्ठता के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया है। . उपरोक्त परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा

आर.एन. आर.

(१) AIR १ ९९ १ एस.सी. 2010